के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के बारे

दैनिक जागरण 23-09-14

1.15 लाख वार्डों का बनेगा मास्टरप्लान

राज्य ब्यूरो, पटना : शहरों के मास्टरप्लान के बाद अब सरकार ने गांवों के मास्टरप्लान बनाने का भी फैसला लिया है। 'हमारा गांव, हमारा विकास' योजना का सोमवार को शुभारंभ करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि 8,406 ग्राम पंचायतों के करीब 1.15 लाख वार्डों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने दो माह के अंदर इसे तैयार कर लेने का निर्देश दिया। प्रत्येक मास्टर प्लान पर 6205 रुपये की राशि खर्च होगी।

मिश्रा ने कहा कि जिनके लिए योजना बनती है, उन तक योजना का लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए आम लोगों के सहयोग से हर वार्ड का मास्टर प्लान बनेगा। चिंता का विषय यह है कि ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी नहीं हो रही। जबतक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, गांवों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। 'हमारा गांव, हमारा विकास' योजना के तहत ग्रामीण खुद तय करेंगे उनके गांव में कौन से विकास कार्य हों। श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में 'इन्टेन्सिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज' विषय पर आयोजित कार्यशाला में मंत्री ने कहा कि इस मास्टर प्लान के आधार मनरेगा का 2015-16 का बजट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एसएम राजू ने कहा कि संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी के प्रतिनिधि तीन दिनों तक वार्ड में रहकर मास्टर प्लान बनाएंगे।

अब एक प्लान के तहत गांवों के विकास

अबतक केवल शहरों का मास्टर प्लान बनता रहा है। गांवों के मास्टर प्लान बनेंगे, जिनका उपयोग सभी विभाग करेंगे। पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों को ध्यान में रख इसे तैयार किया जाएगा। उद्देश्य गांवों का बेहतर विकास करना है।

-नीतीश मिश्रा, ग्रामीण विकास मंत्री

गैरहाजिर थे 14 डीडीसी व 250 बीडीओ : कार्यशाला में 14 डीडीसी और करीब 250 बीडीओ मौजूद नहीं थे। मंत्री ने खासकर जाले, बाराचट्टी, रामनगर एवं कदवा के बीडीओ का नाम पुकारा। चारों मौजूद नहीं थे। उन्होंने सचिव को इन चारों की अनुपस्थिति का कारण पता कर लेने कहा।

पर राशि खर्च होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार ने अधिकारियों का उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया।